



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 25 फरवरी, 2004/6 फाल्गुन, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रधिसूचना

शिमला-171004, 25 फरवरी, 2004

संख्या वि०स०-गवर्नमेंट बिल/1-14/2004.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004

(2004 का विधेयक संख्यांक 4) जो आज दिनांक 25 फरवरी, 2004 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाजटा,
सचिव।

हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (1968 का 24) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 27 जनवरी, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 40 में,— धारा 40 का संशोधन।

(i) उप-धारा (2) में, विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) अन्य विक्रय या माल के विक्रय के भागों, जिनके अन्तर्गत लाटरी टिकट भी हैं, जिनकी बाबत आवर्त की कटौती, व्यापारी के सकल आवर्त से, धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन उसके करायेय आवर्त की संगणना करते समय, की जा सकेगी;” और

(ii) उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (3) जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

“(3) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी सरकार लाटरी टिकटों के प्रयोजन के लिए, हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रारम्भ की तारीख से, पूर्व प्रकाशन के बिना, भूतलक्षी प्रभाव से उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन नियम बना सकेगी।”

3. मूल अधिनियम की अनुसूची “क” में मद संख्या 72 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची “क” मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्:— का संशोधन।

“73. लाटरी टिकटें।”

4. मूल अधिनियम की अनुसूची “ख” में मद संख्या 69 का लोप किया जाएगा। अनुसूची “ख” का संशोधन।

2004 के 5. (1) हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004
अध्यादेश का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।
संख्यांक 1
का निरसन
और
व्यावृत्तियां ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में लॉटरी टिकटों की बिक्री को पुनः आरम्भ करने तथा उनकी बिक्री पर बिक्रय कर उद्बुद्धि करने का विनिश्चय किया गया था तथापि हिमाचल प्रदेश साधारण बिक्रय कर अधिनियम, 1968 की धारा 7 के अधीन लॉटरी टिकटों का बिक्रय कर उद्बुद्धि में छूट प्राप्त थी। इसलिए लॉटरी टिकटों पर बिक्रय कर उद्बुद्धि करने के लिए उपरोक्त अधिनियम को यथोचित रूप में संशोधित करना अनिवार्य समझा गया था।

2. क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश साधारण बिक्रय कर अधिनियम, 1968 (1968 का 24) में तुरन्त संशोधन करना अनिवार्य हो गया था इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा हिमाचल प्रदेश साधारण बिक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का अध्यादेश संख्यांक 1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन 24 जनवरी, 2004 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण) में तारीख 27 जनवरी, 2004 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

3. यह विधेयक, उपर्युक्त अध्यादेश को, बिना किसी उपान्तरण के, प्रतिस्थापित करने के लिए है।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला

तारीख : फरवरी, 2004.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर, राजकोष को लगभग 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वार्षिक आय होगी। क्योंकि विधेयक के उपबन्ध विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रशासित किए जाएंगे, इसलिए राजकोष पर कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को, कराधेय आवर्त की संगणना करते समय व्यौहारी के सकल आवर्त से, लाँटरी टिकटों के विक्रय के भाग से कटौती करने की बाबत नियम बनाने और ऐसे नियमों को, पूर्व प्रकाशन के बिना भूतलक्षी प्रभाव से, हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रारम्भ की तारीख से, बनाने के लिए सशक्त करता है ताकि इस संशोधन अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन विरचिन किए जाने वाले नियमों के कार्यान्वयन के बीच किसी प्रकार के व्यवस्था क्रमभंग (इन्टर-रैगनस) से बचा जा सके। लाँटरी टिकटों की विक्री की विशेष प्रकृति के दृष्टिगत शक्तियों का यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति संख्या ई0 एक्स0 एन0-एफ(10)4/2003]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 4 of 2004

**THE HIMACHAL PRADESH GENERAL SALES TAX
(AMENDMENT) BILL, 2004**

(As introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No. 24 of 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Act, 2004.

Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 27th day of January, 2004.

24 of 1968

2. In section 40 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (hereinafter referred to as the 'principal Act'),—

Amendment of section 40.

(i) in sub-section (2), for the existing clause (d), the following shall be substituted, namely :—

“(d) the other sales or parts of sales of goods including lottery tickets, turnover in respect of which may be deducted from a dealer's gross turnover, in computing his taxable turnover under sub-section (3) of section 6;” and

(ii) after sub-section (2), the following sub-section (3) shall be added, namely :—

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Government may, for the purpose of lottery tickets, make rules under clause (d) of sub-section (2), without previous publication, with retrospective effect from the date of commencement of the Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Act, 2004.”

3. In Schedule 'A' to the principal Act, after item No. 72, the following item shall be added, namely :—

Amendment of Schedule 'A'.

“73. Lottery tickets.”

4. In Schedule 'B' to the principal Act, item No. 69 shall be omitted.

Amendment of Schedule 'B'.

Repeal of
Ordinance
No. 1 of
2004 and
savings

5. (1) The Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It was decided to re-introduce sale of lottery tickets in the State of Himachal Pradesh and to levy sales tax on the sale of lottery tickets at the rate of 20%. However, under section 7 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968, lottery tickets were exempted from sales tax. Thus, in order to levy sales tax on lottery tickets, it was considered essential to suitably amend the Act *ibid*.

2. Since the Legislative Assembly was not in session and amendment of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 2004 (H.P. Ordinance No. 1 of 2004) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 24th January, 2004, which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) dated 27th January, 2004. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

3. This Bill seeks to replace the said Ordinance without any modification.

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
The February, 2004.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill if enacted will yield additional annual income of rupees two crores approximately to the State exchequer. As the provisions of the Bill will be administered by the existing Government machinery, therefore, no additional expenditure will be incurred from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill empowers the State Government to make rules about deduction of the part of the sale of lottery tickets from the dealer's gross turnover in computing the taxable turnover and to make such rules without previous publication with retrospective effect, from the date of commencement of the Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Act, 2004, for avoiding any inter-regnum between the operation of the provisions of this amendment Act and the rules to be framed thereunder. This delegation of powers is essential and normal in character in view of the special nature of sale of lottery tickets.

RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION

File No. EXN-F (10) 4/2003

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Bill, 2004, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.